ICAI/012/CP&GFM/TP – ULB

आदरणीय निदेशक महोदय / महोदया
नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA)
झारखंड

विषय: शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies-ULBs) के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम / वेबिनार आयोजित करने का प्रस्ताव

स्थानीय स्वशासन के स्तर पर बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन, समय की आवश्यकता है क्योंकि समय के साथ स्थानीय निकायों की भूमिका और जिम्मेदारियां विकसित हुई हैं और ये निकाय देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रभावी और कुशल तरीके से सार्वजनिक निधियों के प्रबंधन, निर्णय लेने, संचालन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करती है जो अंततः स्थानीय निकायों को नागरिकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने, देश में बुनियादी ढांचे के विकास और पूंजी बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से धन जुटाने में मदद करेगी।

भारत सरकार ने ULBs में वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (NMAM), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM), AMRUT, स्मार्ट सिटी योजना आदि जैसी प्रमुख विकास योजनाएं पर ध्यान केंद्रित किया है।

वित्त आयोगों ने भी ULBs में accrual लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया। सुधारों को तेजी से ट्रैक करने के लिए, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त के रूप में पिछले वर्ष के अलेखापरीक्षित वार्षिक खातों और पिछले वर्ष से पहले वर्ष के लेखा परीक्षित खातों की ऑनलाइन उपलब्धता की सिफारिश की जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की भूमिका:

ICAI राष्ट्र की सेवा करने वाले लेखा और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। ICAI, राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में, चल रहे लेखांकन सुधारों और वित्तीय रिपोर्टिंग और सार्वजनिक वित्तीय सुधार में तथा ULBs सहित विभिन्न सरकारी संस्थाओं/ विभागों के प्रबंधन में भी शामिल है। ICAI की देश के tier I और II शहरों में 160 से अधिक शाखाएं हैं।

ICAI की सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति (CP&GFM) स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानक (Accounting Standards for Local Bodies-ASLBs) जारी करती है (आज तक जारी 30 ASLBs https://www.icai.org/post.html?post_id=1527 पर उपलब्ध हैं)। समिति विभिन्न कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके, लेखांकन सुधारों के लाभों के बारे में बड़े पैमाने पर संबंधित अधिकारियों और समाज को संवेदनशील बनाने में भी शामिल है। इस दिशा में, कई व्याख्यान विकसित किए गए हैं जो https://icaitv.com/category.php?cat_id=22 पर उपलब्ध हैं।

"ICAI Bhawan", Indraprastha Marg,
Post Box No. 7100, New Delhi - 110 002. India
Phone: (+91) (011) 3989 3989 | Fax: (+91) (011) 3011 0581
Email: icaiho@icai.org | Website: http://www.icai.org

अतीत में, ICAI की अनुसंधान शाखा, ICAI एकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (ICAI ARF) ने दिल्ली नगर निगम और कोलकाता नगर निगम को उनकी रूपांतरण परियोजना और वित्तीय निगरानी सुधारों में सहायता की थी।

चूंकि सरकार के वित्तीय अनुदान को ULBs में वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन में सुधार से जोड़ा गया है, इसलिए ULB के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण की तत्काल और निरंतर आवश्यकता है। इस दिशा में, CP&GFM ULBs को 'वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही' के विशेष संदर्भ में ULBs के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम / वेबिनार आयोजित करने के लिए अपना प्रस्ताव दे रहा है।

इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विशेष रूप से संरचित किया जाएगा ताकि प्रतिभागियों को स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधारों के महत्व के संबंध में अपने ज्ञान को अद्यतन करने का अवसर प्रदान किया जा सके। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सुधारों के कार्यान्वयन में आने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों को हल करने में भी मदद करेंगे और शहरी बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने और स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में भी मददगार होगा।

इस तरह के कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के अनुभव सीखे गए पाठों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करते हैं। संलग्न अनुलग्नक को विस्तृत प्रस्ताव के लिए संदर्भित किया जा सकता है। कर्मचारियों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम संरचना को पारस्परिक रूप से अंतिम रूप दिया जा सकता है। कार्यक्रम/वेबिनार क्षेत्रीय भाषा में भी आयोजित किए जा सकते हैं।

हमें उम्मीद है कि यह पहल स्थानीय निकायों में मजबूत और पारदर्शी लेखा ढांचे के लिए एक गुणवत्ता संरचना स्थापित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

हमें इस संबंध में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हमें उम्मीद है कि इस सहयोग से स्थानीय निकायों और समाज को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

धन्यवाद,

सादर,

CA केमिशा सोनी **CA श्रीधर मुप्पला**
अध्यक्ष **उपाध्यक्ष**
सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति
सचिवालय: 0120-3045985
ई-मेल: cpf.aslb@icai.in; cpf_ga@icai.in

संलग्नक: ऊपरोक्त अनुसार

"ICAI Bhawan", Indraprastha Marg,
Post Box No. 7100, New Delhi - 110 002. India
Phone: (+91) (011) 3989 3989 | **Fax:** (+91) (011) 3011 0581
Email: icaiho@icai.org | **Website:** http://www.icai.org

अनुलग्नक/ Annexure

शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ वेबिनार आयोजित करने का प्रस्ताव	**Proposal for jointly organising training programmes/webinars for staff of Urban Local Bodies**
प्रशिक्षण का विषय: ○ शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही	**Theme of the Training:** ○ Financial Transparency and Accountability in Urban Local Bodies
प्रशिक्षण की अवधि: ○ एक दिन/दो दिन	**Duration of the Training:** ○ One Day/Two Days
लक्षित प्रतिभागी: ○ शहरी स्थानीय निकायों के वित्त और लेखा अनुभागों से जुड़े कर्मचारी। (प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागियों को राज्य/संबंधित शहरी विकास विभाग द्वारा पहचाना और सुझाया जा सकता है)	**Targeted Participants:** ○ Staff associated with Finance and Accounts Sections of Urban Local Bodies. (Participants for the training may be identified and suggested by the State/ respective urban development department)
प्रतिभागियों की संख्या: ○ न्यूनतम 50 प्रतिभागी	**No. of participants:** ○ Minimum 50 participants
प्रशिक्षण पद्धति: ○ प्रशिक्षण एक संवादात्मक रूप में आयोजित किया जाता है और इसमें कई केस स्टडी शामिल हैं। ○ प्रशिक्षण प्रतिभागियों को पृष्ठभूमि सामग्री और संकायों के PPT भी प्रदान किए जाते हैं।	**Training Methodology:** ○ Training is conducted in an interactive form and includes a number of case studies. ○ Training participants are provided the background materials and also the PPTs of the faculties.
संकाय: ○ शहरी स्थानीय निकायों/सरकार, रूपांतरण परियोजनाओं आदि में प्रोद्भवन लेखांकन कार्यान्वयन और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले पेशेवर विशेषज्ञ।	**Faculty:** ○ Faculty comprises of professional experts having relevant experience in the field of accrual accounting implementation and audit in Urban Local Bodies/ Government, conversion projects, etc.

प्रशिक्षण के लिए संभावित विषयों की सूची	List of tentative topics for the Training
परिदृश्य 1: यदि दोहरी प्रविष्टि प्रोद्भवन लेखा प्रणाली को अभी लागू किया जाना है:	Scenario 1: If Double Entry Accrual Accounting System is yet to be implemented:
1. स्थानीय निकायों के लिए प्रोद्भवन लेखांकन ○ मूल बातें और प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के लाभ ○ नकद बनाम प्रोद्भवन लेखा प्रणाली	1. Accrual Accounting for Local Bodies ○ Fundamentals & Benefits of accrual accounting system ○ Cash vis-à-vis accrual accounting system
2. ULB में लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली ○ लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति ○ लेखांकन सुधारों को अनिवार्य करने की आवश्यकता: मौजूदा कानूनों और नियमों में संशोधन ○ ULB में लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली में सुधार करने में ICAI और CA कैसे सहायता कर सकते हैं?	2. Accounting and Auditing System in ULBs ○ Current status of accounting and auditing system ○ Requirement to mandate accounting reforms: amendments in existing laws & rules ○ How can ICAI and CAs support in improving accounting and auditing system in ULBs
3. शहरी स्थानीय निकायों के खातों को नकद प्रणाली से दोहरी प्रविष्टि प्रोद्भवन लेखा प्रणाली में परिवर्तित करना ○ रूपांतरण प्रक्रिया में व्यावहारिक मुद्दे/चुनौतियां ○ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और प्रकटीकरण ○ केस स्टडी/सफलता की कहानियां	3. Conversion of accounts of ULBs from cash system to double entry accrual accounting system ○ Practical issues/ challenges in conversion process ○ Significant accounting policies and disclosures ○ Case studies/ success stories
4. प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के तहत प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करना ○ आस्तियों और देनदारियों के प्रारंभिक शेष का निर्धारण ○ आवश्यक समायोजन किए जाने चाहिए ○ किए जाने वाले महत्वपूर्ण खुलासे	4. Preparation of Opening Balance Sheet under accrual accounting system a. Determination of opening balances of assets and liabilities b. Necessary adjustments to be made c. Significant disclosures to be made

5. लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के तहत खातों के चार्ट का पुनर्गठन	5. Restructuring of chart of accounts under accrual system of accounting
6. कम्प्यूटरीकृत वातावरण में दोहरी प्रविष्टि प्रोद्भवन लेखा प्रणाली का कार्यान्वयन o कार्यान्वयन के लिए IT पैकेज का उपयोग करना	6. Implementation of double entry accrual accounting system in computerised environment o Using IT packages for implementation
<u>परिदृश्य 2: यदि डबल एंट्री प्रोद्भवन लेखा प्रणाली लागू की गई है:</u>	**Scenario 2: If Double Entry Accrual Accounting System has been implemented:**
1. सीखे गए सबक और प्रोद्भवन लेखा सुधारों की स्थिरता o मौजूदा लेखा प्रणाली का विश्लेषण o गैप विश्लेषण और संभावित समाधान	1. Lessons Learnt & Sustainability of Accrual Accounting Reforms o Analysis of existing accounting system o Gap Analysis & possible solutions
2. प्रोद्भवन आधारित वित्तीय विवरणों की व्याख्या o समस्याओं की पहचान और विश्लेषण करने के लिए वित्तीय विवरणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है o निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों का महत्व	2. Interpreting Accrual Based Financial Statements o How financial statements can be used to identify and analyse problems o Importance of Financial Statements in Decision Making
3. शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा o मौजूदा ऑडिटिंग सिस्टम का विश्लेषण o गैप विश्लेषण और संभावित समाधान ▪ लेखा परीक्षा समिति की भूमिका ▪ उन्नत लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग ▪ लेखा परीक्षा में पेशेवरों की भूमिका ▪ लेखापरीक्षा में नैतिकता	3. Audit in Urban Local Bodies o Analysis of existing auditing system o Gap Analysis & possible solutions ▪ Role of Audit Committee ▪ Enhanced audit reporting ▪ Role of professionals in audit ▪ Ethics in audit
4. IT वातावरण में ULB का लेखा परीक्षण o कम्प्यूटरीकृत सहायता प्राप्त लेखा परीक्षा तकनीक (CAAT)	4. Auditing ULBs in IT environment o Computerised Aided Audit Techniques (CAAT)
5. भारत में आत्मनिर्भर नगर निकाय बनाना o राजस्व वृद्धि	5. Making Self-Sufficient and Self-Sustainable Municipal Bodies in India o Revenue Augmentation

○ वित्त जुटाने के नवीन और नए साधन ▪ मेजेनाइन फाइनेंसिंग ▪ सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) ▪ नगर बांड	○ Innovative and new means of raising finances ▪ Mezzanine financing ▪ Public Private Partnership (PPP) ▪ Municipal Bonds
6. स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (ASLBs) ○ ASLBs का औचित्य और महत्व ○ ASLBs के कार्यान्वयन से ULBs कैसे लाभान्वित हो सकते हैं	6. Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) ○ Rationale and Significance of ASLBs ○ How can ULBs benefit from implementation of ASLBs
7. स्थानीय सरकार कराधान मामले: स्थिति और अनुपालन ○ GST ○ TDS	7. Local Government Taxation Matters: Status and compliances ○ GST ○ TDS
8. नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों की जवाबदेही में सुधार और नगरपालिका बजट में उनकी भागीदारी ○ सहभागी बजटिंग ○ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदर्शन मापन और रिपोर्टिंग	8. Improving Accountability of ULBs towards Citizens and their participation in Municipal Budgeting ○ Participatory Budgeting ○ Performance Measurement and Reporting by ULBs
9. स्मार्ट सिटी और म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए आगे का रास्ता	9. Way forward for Smart Cities and Municipal Bonds
वित्तीय सम्भावनाए:	**Financial Implications:**
➢ शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में, व्यय राज्य सरकार/संबंधित शहरी विकास विभाग और ICAI द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जा सकता है जैसा कि नीचे सुझाया गया है: • ICAI द्वारा वहन की जाने वाली लागत: ○ संकाय के TA/DA खर्च ○ संकाय को मानदेय ○ प्रतिभागियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री	➢ In case of physical training programme, expenditure may be borne jointly by State Government/respective Urban Development Department and ICAI as suggested below: • Cost to be borne by ICAI: ○ TA/DA expenses of Faculty ○ Honorarium to Faculty ○ Background material for participants

• राज्य सरकार/संबंधित शहरी विकास विभाग द्वारा वहन की जाने वाली अन्य रसद व्यवस्था के संबंध में लागत।	• Cost with regard to other logistic arrangements to be borne by the State Government/ respective urban development department.
➢ आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में, राज्य सरकार/संबंधित शहरी विकास विभाग पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस मामले में, मंच से संबंधित सभी लागत और संकायों को मानदेय ICAI द्वारा वहन किया जाएगा।	➢ In case of virtual training programme, there shall be no financial implications on State Government/respective Urban Development Department. In that case, all the cost pertaining to platform and honorarium to faculties shall be borne by the ICAI.